DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 9 मार्च 2024

DATED

फतेहपुर बेरी का पुराना तालाब ₹50 लाख से संवारा जाएगा

■ एनबीटी न्यूज, छतरपुर

फतेहपुर बेरी के कई सौ साल पुराने जोहड़ (पुराना तालाब) को बचाने की मांग लोग लंबे समय से उठा रहे हैं। अब डीडीए ने जोहड़ के पानी की सफाई और इसके सौंदर्यीकरण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस काम में करीब 50 लाख रुपये खर्च होंगे।

जोहड़ की बदहाल स्थिति को लेकर एनबीटी ने भी कई बार खबरें प्रकाशित की हैं। जोहड़ के संरक्षण की लगातार मांग उठा रहे तेजपाल, लालूराम और ऋषि पाल महाशय ने बताया है कि यह जोहड़ उनके गांव की संस्कृति से जुड़ा है। लेकिन, अब यह तालाब दलदल में तब्दील

एनबीटी ने भी अवसर उठाया इसका मुद्दा

हो चुका है। साथ ही यहां गंदगी भी फैली रहती है।

डीडीए ने 50 लाख से अधिक रुपये लागत की योजना तैयार की है। इसके तहत पानी की सफाई, बाउंड्री, लोगों के बैठने का लिए बेंच, हरियाली और सौंदर्यीकरण पर काम शुरू हो गया है। इस पर इलाके के लोगों ने खुशी जताई है।

पहाड़गंज : गंदे पानी की सप्लाई, खरीदकर करना पड़ रहा गुज़ारा

■ एनबीटी न्यूज, पहाड़गंज

डीडीए के LIG फ्लैट की कॉलोनी रानी झांसी कॉम्प्लेक्सके करीब 150 फ्लैटों में पिछले 10 दिन से पीने के गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों ने बताया कि लीकेज के कारण सीवर का पानी जल बोर्ड के पाइप में जा रहा है। शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या को अनदेखी कर रहे हैं।

एनबीटी सुरक्षा कवच मंदिर मार्ग से जुड़े राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि फ्लैटों की 11 से अधिक बिल्डिंगों में पीने के गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पानी इतना अधिक गंदा और बदबूदार है कि उसे किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है। पिछले दिनों सीवर की नई लाइन बिछाई गई थी। उसका बहाव गलत दिशा में है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---नई दिल्ली, 9 मार्च, 2024 दैनिक जागरण--DATED----------

यातायात सुगम बनाने के काम में प्रगति, खेल के मामलों में नहीं

जागरण एजेंडा
रिव्यू

आशीष गुप्ता ● पूर्वी दिल्ली

राजधानी के पिछड़े इलाकों में शुमार उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में यातायात सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। पांच साल में यहां जाम खत्म करने और यातायात सुगम बनाने की दिशा में काफी काम हुआ है। किंतु कालोनियों के विकास की राह लोग अब तक ताक रहे हैं। सड़क, पानी और सीवर सरीखी मूलभूत सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। यहां के राष्ट्रीय मुद्दों में शामिल निर्मल यमुना का मामला अब तक सपना ही है। अमृत योजना के तहत वजीराबाद एसटीपी बनाने के लिए फंड की व्यवस्था कराने से आगे कोई काम नहीं हो पाया। कालोनियों के ढांचागत विकास का काफी काम रह गया। एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा। राज्य स्तरीय मुद्दों में से परिवहन व्यवस्था में सुधार के कुछ कदम उठे हैं। मेट्रो का विस्तार हो रहा है, लेकिन बसों का नेटवर्क मजबूत नहीं हुआ है। खेल सुविधाओं की दिशा में योजनाएं बनीं, किंतु धरातल पर उनका लागू होना बाकी रह गया।

वजीराबाद पुल के पास यमुना के किनारे पड़ा कूड़ा ● जागरण आर्काइव

कालोनियों में नहीं हो सका विकास, यहां के रास्त हैं संकरे

उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनधिकृत कालोनियां हैं। इनमें बड़ी आबादी रहती है। सोनिया विहार, श्रीराम कालोनी, करावल नगर, खजूरी खास, शिव विहार, सादतपुरी, सभापुर, मंडोली, सबोली, भजनपुरा, घौंडा, ब्रह्मपुरी, वेलकम समेत अधिकतर इलाकों में गलियों के रास्ते संकरे और जर्जर हैं। यहां गलियों में जाम भी लगता है। इन क्षेत्रों में पानी निकास की उचित व्यवस्था नहीं है। नालों की सफाई चुनौती बनी हुई है। गोकलपुरी नाला हर वक्त गंदगी से पटा रहता है। इसकी वजह से क्षेत्रों में जलभराव की समस्या है। कई इलाकों में सीवर नहीं है। सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार की दुर्दशा को दूर करने के लिए लोकसभा में आवाज उठा चुके, जिसके लिए 250 करोड़ रुपये बजट भी मिला, पर काम फिर भी नहीं हो पाया। सीमापुरी में अतिक्रमण की समस्या है। बुराड़ी और तिमारपुर में भी परिस्थितियां बहुत बदल नहीं पाई हैं। पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर बाकी क्षेत्रों में विकास के लिए कोई योजना नहीं बनी। राज्य सरकार से समन्वय की कमी इस क्षेत्र पर भारी पड़ती दिखी।

राजधानी की लाइफ लाइन यमुना अब तक नहीं हो सकी साफ

राष्ट्रीय राजधानी के लिए यमुना लाइफ लाइन है। इसका पानी यहां रह रहे लोगों की प्यास बुझाता है। किंतु इस नदी की दशा सुधारने का काम नहीं हो पाया है। यमुना लगातार मैली होती चली गई। इसे प्रदूषित करने वालों पर लगाम लगाकर नदी को स्वच्छ करने पर काम नहीं हो सका। इसका पानी हाथ में लेने लायक भी नहीं है। एनजीटी की तमाम चिंताओं के बावजूद काम नहीं होने का नतीजा है कि सिग्नेचर ब्रिज के आसपास गंदे पानी की वजह से यमुना में झाग दिखाई देता है। कहते हैं प्रवाह बेहतर हो जाय तो नदी अपने जख्मों को खुद ठीक कर लेती है। इस दिशा में भी कोई काम नहीं हो सका है। वजीराबाद एसटीपी बनाने के लिए अमृत योजना के तहत 1210 करोड़ रुपये का प्रविधान जरूर हुआ और निर्माण चल रहा है। किंतु सिर्फ इससे यमुना को निर्मल बनान मुमकिन नहीं है।

सबोली हाल्ट को आदर्श बना रहे, पर नहीं रुक रहीं एक्सप्रेस ट्रेनें

घनी आबादी वाले उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहां एक भी बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, जिस पर देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो सके। इसलिए यहां के लोग नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार ट्रेनें पकड़ते हैं। ये तीनों स्टेशन इस क्षेत्र से दूर हैं। इसे देखते हुए सबोली हाल्ट को आदर्श स्टेशन बनाने की दिशा में काम करने का मुद्दा दैनिक जागरण ने सांसद को दिया था। कुछ माह पहले प्लेटफार्म उठाने, बेंच व शेड लगाने का काम शुरू हुआ, जोकि जारी है। इस हाल्ट पर सात पैसेंजर रुकती हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनें मांग के बावजूद नहीं रुकती हैं।

कई पार्क हुए विकसित, पार्किंग की समस्या बरकरार

पार्क विकसित करने को लेकर इस संसदीय क्षेत्र में काम हुआ है। रोहतास नगर में मिल की जमीन पर दो पार्क विकसित किए गए हैं। यमुना किनारे रिवर फ्रंट के तौर पर 272 एकड़ जमीन को विकसित करने का काम प्रगति पर है। इसमें 11 झीलें, साइकिलिंग ट्रैक, ओपन जिम और बहुत कुछ है। वेलकम झील पार्क अमृत योजना के तहत आंशिक रूप से विकसित हुआ, लेकिन उजड़ भी गया। क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है, इसका हल नहीं निकला।

हर तरफ फैली है गंदगी : स्वच्छता के मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा है। यहां पाश इलाकों में गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। यमुना विहार बस डिपो के सामने कूड़े का अंबार रहता है। खजूरी खास, सोनिया विहार, करावल नगर, सभापुर गांव, नंद नगरी, मंडोली, गसेकलपुरी में सड़कों पर ही गंदगी नजर आती है।

हाईवे बनने से होगी सुविधा

पिछले लोस चुनाव में यातायात की समस्या बड़ा मुद्दा था। लोगों की मांग पुश्ता और वजीराबाद रोड को जाम मुक्त बनाने की थी। केंद्र पुश्ता रोड पर दिल्ली-सहारनपुर हाईवे बना रहा है। 90 प्रतिशत काम हो चुका है। इसमें 1100 करोड़ रुपये खर्च हुए। पूरे हाईवे को बनाने में चार हजार करोड़ लग रहे हैं। वजीराबाद रोड पर जाम खत्म करने को सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो कारिडोर बनाया जा रहा है।

मेट्रो का विस्तार, बसों की कमी

मौजपुर से मजलिस पार्क तक मेट्रो लाइन के विस्तार हो रहा है। इससे कुछ हद तक यमुना विहार, करावल नगर, खजूरी खास, भजनपुरा, सोनिया विहार जैसे क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। किंतु इस क्षेत्र में बसों का नेटवर्क उतना बेहतर नहीं है, लोगों को यहां से राजधानी के ही अन्य हिस्सों में जाने के लिए मशक्कत करती पड़ती है। इस कारण से यहां अवैध आटो और ई-रिक्शा सड़कों पर हैं।

स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनने बाकी

जग प्रवेश चंद अस्पताल के पास मिनी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाने का प्रस्ताव डीडीए से स्वीकृत है। पांच एकड़ जमीन चिह्नित है, लेकिन भू-उपयोग के पेच में मामला फंसा है। यह भूमि पार्क के लिए निर्धारित है। इस जमीन पर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाने के लिए दूसरी जगह पार्क बनाना होगा। वो जमीन नहीं मिल रही और योजना अटकी है। इसी तरह बुराड़ी में प्रस्तावित स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का प्लानिंग के स्तर पर लटका हुआ है।

यमुना सफाई व कालोनियों के विकास की दिशा में काम करने का काफी प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग न मिलने से उतना काम नहीं हो पाया, जितने की जरूरत है। कई बार प्रस्ताव बनाए गए और संसद में मुद्दे उठाए गए। सोनिया विहार के लिए बजट दिलवाया, लेकिन उससे जारी करने का काम राज्य की एजेंसी को करना था, जो नहीं किया गया। मुस्तफाबाद व गोकलपुरी क्षेत्र में सीवर कार्य शुरू कराया था, लेकिन अड़चनों के चलते नहीं हो पाया। यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर मार्च पर काम किया है।

– मनोज तिवारी, सांसद, उत्तर पूर्वी दिल्ली

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 मार्च, 2024 -DATED----------

दिल्ली को फूलों का शहर बना रही है एनडीएमसी: उपराज्यपाल

- दो दिवसीय पुष्प महोत्सव में 14 हजार से ज्यादा फूलों के पौधे कर रहे हैं लोगों को आकर्षित
- पिरामिड और विभिन्न कलाकृतियां बनाकर रंग बिरंगे फूलों को किया गया है प्रदर्शित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली का दिल कनाट प्लेस और इसमें रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी ने सभी का मन मोह लिया। एनडीएमसी द्वारा आयोजित दो दिवसीय पुष्प महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने एनडीएमसी को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि शहर की सुंदरता को सुधारने के किए गए नव प्रयोगों के तहत 'राजधानी को फूलों के शहर और आनंद के शहर' में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल जैसे फूलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे इलाकों के लोग अक्सर इन कार्यक्रमों में आए।

इससे एनडीएमसी के प्रयासों को सच्ची पहचान मिली और एक मान्यता मिली। सक्सेना ने पिछले साल एनडीएमसी द्वारा शुरू किए गए ट्यूलिप पौधारोपण की प्रशंसा की और कहा कि इन प्रयासों से इस साल पूरी दिल्ली में पांच लाख ट्यूलिप खिले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज तक हम ट्यूलिप का आयात कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमसी ने हाईब्रिड ट्यूलिप की खेती के लिए एक ग्रीनहाउस स्थापित किया है। भविष्य में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और ट्यूलिप का आयात बंद कर सकेंगे।' उन्होंने दिल्ली में एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए समेत अन्य विभागों से फ्लावर शो की प्रतिस्पर्धा आयोजन का सुझाव भी दिया। एनडीएमसी चेयरमैन अमित यादव ने बताया कि 35 से अधिक किस्मों के हजारों फूल इस महोत्सव में प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पुष्प महोत्सव को फूल के प्रदर्शन और सजावट के लिए 1 अलग-अलग वर्गों में विभाजित किय गया है। पुष्प महोत्सव सभी के लि खुला है और प्रवेश निशुल्क है।

कनाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी द्वारा आयोजित फ्लावर फेस्टिवल का उदघाटन करने के बाद अवलोकन करते उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना व साथ में चेयरमैन अमित यादव, व उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ● सौजन्य: राज निवास

फूलों से बनी आकृतियां कर रही हैं आकर्षित

एनडीएमसी ने पुष्प महोत्सव को आकर्षित बनाने के लिए पशु-पक्षियों की पुष्प आकृतियां, रंगीन पुष्प बोर्ड, ट्रे गार्डन, बड़े आकार की हैंगिंग टोकरियां, टेरारियम, इकेबाना, पूर्वी और पश्चिमी शैली जैसी फूलों की सजावट को प्रदर्शित किया है। इसमें पिरामिड, हार्ट शेप, सेल्फी प्वाइंट, शंक्वाकार पुष्प संरचना, पुष्प सिलेंडर आदि कलाकृतियां शामिल हैं। पार्क के केंद्र में शाम को रंगीन रोशनी के साथ एक संगीतमय फव्वारा भी लोगों को खासा आनंदित कर रहा है। जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही है।

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MARCH 10, 2024

LG inaugurates flower festival at CP

New Delhi: New Delhi Municipal Council is organising a two-day flower festival at Central Park in Connaught Place on March 9 and 10.

LG VK Saxena, who inaugurated the festival, said a competition of flower shows will soon be organised between NDMC, MCD and DDA to create innovative ideas in the field of beautification of the city.

While giving the outline of the flower show, NDMC chairman Amit Yadav said the flower festival has been divided into 18 different sections for flowering display and decoration. Entry to the festival is free. TNN

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
रविवार
10 मार्च 2024

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप

नई दिल्ली। बुराड़ी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। एसडीएम ने अतिक्रमण रोकने के लिए सरकारी जमीन पर स्टे भी लगा दिया। शिकायतकर्ता राम अवतार त्यागी ने बताया कि खसरा नंबर 527 पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली सरकार से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NEW DELHI
MONDAY
MARCH 11, 2024

Delhi WTC to soon be ready for business

Soumya Chatterjee
letters@hindustantimes.com

Delhi's World Trade Centre will primarily have the offices of private corporations, government departments, and public sector undertakings. ARVIND YADAV/HT PHOTOS

NEW DELHI: Over the last few weeks, metallic sheets that shielded a massive construction site at Nauroji Nagar in south Delhi for close to three years have begun to be gradually removed, slowly revealing a first glimpse of the national capital's first World Trade Centre (WTC) — the sparkling glass façade of 12 newly built 10-storey towers.

The site, which is spread across 25 acres of land, have replaced 600-odd residential quarters that housed government employees for close to five decades — one of seven general pool residential accommodation (GPRA) colonies in the city, along with Sarojini Nagar, Nauroji Nagar, Kasturba Nagar, Netaji Nagar, Srinivaspuri, Mohammadpur, and Thyagraj Nagar, which has been redeveloped.

The project, licenced by New York's World Trade Centre Association (WTCA), has 3.4 million sq ft in commercial area, and selling space here raises much of the funds required for redeveloping the seven GPRA colonies.

The cost for ₹32,835 crore for the seven GPRA, while the WTC project cost an estimated ₹2,694 crore, officials said.

"As of now, four of the 12 buildings are ready to be occupied. Two Central departments have already started functioning from the complex," an official from NBCC — a public sector undertaking under the Union ministry of housing and urban affairs — said on condition of anonymity.

Senior NBCC officials said the target is to complete the construction of the WTC and the sale of commercial space by the end of the current financial year, with 80% of the space already sold, with some of the successful bidders including HDFC, GAIL, Petronet LNG, and Oil India.

"WTC's accreditation has raised its marketability, and hence, we are confident of finishing the entire sale by the end of the month," the official quoted above said, adding that the proximity of the airport, Hazrat Nizamuddin railway station, Central Secretariat, Bhikaji Cama Place, and the Delhi Metro make it an attractive destination.

What the new WTC means for Delhi-NCR

WTCA currently has member properties in more than 90 countries. Mumbai was the first Indian city to have a WTC, and currently, more than 30 Indian cities have such properties, including two cities in the National Capital Region —Noida and Gurugram.

The foundation stone was laid in May 2018 after WTCA granted NBCC the licence in September 2017.

This space will primarily office private corporations, government departments, and public sector undertakings. In addition, there will be a landscaped retail and food and beverage plaza with terrace gardens, and will have a three-layer underground parking structure with a capacity for 8,000 cars.

In addition, a four-story school building will be given to the civic body as part of social infrastructure.

Offering a large floor area for offices in the heart of south Delhi makes WTC a "notable development", said realty experts, because in the last decade, noting that many private companies seeking such office spaces have chosen Gurugram and Noida over the national capital. "The strategic location with frontage on Ring Road, with power backup, green design principles, and ample parking solutions collectively make this project an option worth considering for businesses in search of accessible office spaces," said G Hari Babu, national president of the National Real Estate Development Council (NAREDCO).

Vibhor Jain, managing director at Cushman and Wakefield, said, "Delhi has always been a supply crunch market from a commercial office availability point of view, and this is after a long time that a large floor office is available due to this project."

He said that the location alone cannot guarantee the project's success, but a WTC with the right mix of amenities is a good destination in itself. Referring to the existing Ansal Plaza and Bhikaji Cama complex near the project, he said those properties do not have the qualities to attract top-tier clients and lack the required modern amenities like power backup, centralised parking and civic upkeep.

How the project will affect traffic on Ring Road

WTC is located right on Ring Road, which serves as a major transportation artery connecting various traffic hotspots such as DND-Ashram, Lajpat Nagar, South Extension, Moti Bagh, Dhaula Kuan, Rajouri Garden, and Punjabi Bagh, and is located close to two of the Capital's largest medical facilities —Safdarjung Hospital and AIIMS.

In August 2018, the Delhi high court stayed the WTC project for two years, citing environmental concerns, including apprehensions about the traffic situation in the area. The stay was finally lifted in February 2020, after the court was satisfied with no-objection certificates from the concerned departments and the compensatory afforestation promised by the government agencies.

However, experts feel that an increase in traffic volume on Ring Road is unavoidable, given the project's magnitude.

"There might be a need to increase (traffic) capacity for making U-turns below the Bhikaji Cama flyover," Sewa Ram, head of the transport and planning department at School of Planning and Architecture.

Ashok Bhattacharjee, a former director of planning at Delhi's apex traffic and transport body UTTIPEC, said the authorities should ensure there is enough pedestrian access to the WTC campus, and explore how the access to public transport such as the Metro and buses can be made easier for officegoers.

In addition, MoHUA and subordinate departments, Delhi Development Authority plan to build a 14-km elevated corridor from INA market on Aurobindo Marg to the Mahipalpur underpass, which will serve as an alternative route from and to the airport. Sewa Ram said that this should address some of the traffic concerns.

Green and safety features

The WTC project has an integrated building management system with 100% predictive maintenance of all electrical and mechanical systems. Facility operators can oversee and control all services on one screen. Access to the site and buildings will be restricted via radio-frequency-controlled smart tags for occupants, which will be used for parking, boom barriers, and lifts.

Light poles on the campus will also double as WiFi hotspots and public address systems in times of potential distress. The entire campus will have modern fire detection and response systems. In case of fire, lighting and signage for emergency exits will be automatically turn on, and 10% of the windows will open automatically for smoke extraction. There will be smoke extraction facilities in lifts and lobbies.

Solar panels on rooftops will generate 800 kilowatts of power, and lights in all areas will be sensor-activated to modify energy usage and increase intensity based on requirements. Following the GRIHA-3 energy efficiency rating, the buildings will have a combination of double cavity walls and double-insulated glass, thereby reducing the need for air conditioning.

Officials said the building will follow a zero-waste model for solid waste and water. The facility will have two in-house sewage treatment plants with a combined capacity of 1,800 kilolitres a day. "All used water will be reused for flushing, and the treated sewage will be used for horticulture," a second NBCC officer said.

The basement will have a central waste collection system, in-house compactor facilities, and anti-odour treatment. To capture rainwater, the site has 26 pits, each having a capacity of 66,000 litres.

However, some concerns remain.

"The three levels of basements and edge-to-edge construction in the project means that there is no space to plant trees, and the natural water table of the area in a water-stressed city is disturbed," said Vallari Sheel, an environmentalist based in Delhi.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MARCH 11, 2024 ME OF NEWSPAPERS

Vasudev Ghat to be ready for Varanasi-like aarti soon

Vibha.Sharma@timesgroup.com

Photos: Piyal Bhattacharjee

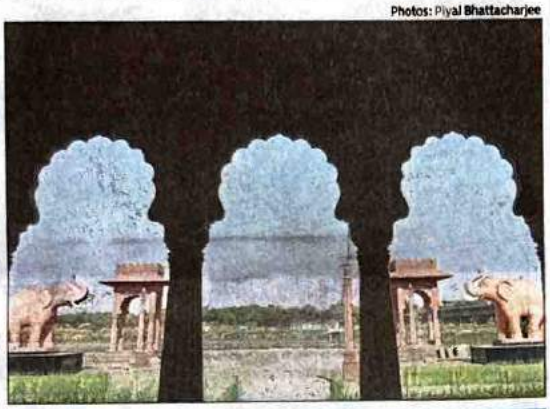

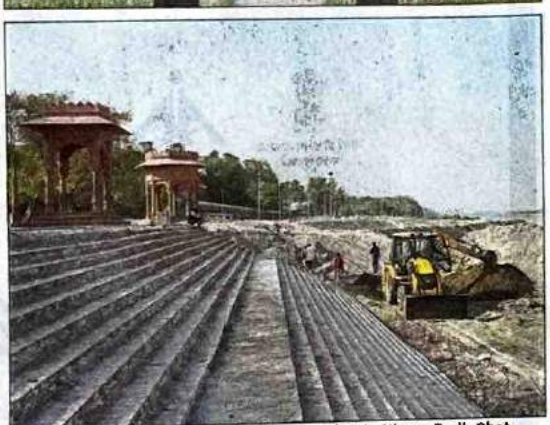

Vasudev Ghat covers the existing Yamuna Ghat to Nigam Bodh Ghat

New Delhi: As the beautification and restoration at Vasudev Ghat nears completion, Delhi Development Authority (DDA) has finalised a plan for organising a regular Yamuna Aarti here like the Ganga Aarti in Varanasi.

TOI visited the place on Friday when silt removal was in progress at the ghat, which is spread over 16 hectares. The pilot is part of DDA's initiative for rejuvenating 66 hectares of ghats from Wazirabad to the Old Railway Bridge on the western bank. Lieutenant governor VK Saxena is likely to inaugurate Vasudev Ghat on Tuesday.

"The horticulture, walkway and restoration work are almost complete. The stress is more on clearing silt so that the river water can reach the steps constructed at the bank and aarti can be performed here regularly. We have already signed an MoU with an organisation that would be performing the aarti every evening," an official said.

The ghat, covering the existing Yamuna Ghat to Nigam Bodh Ghat, is unique among ongoing projects for restoration and rejuvenation of floodplains of river Yamuna, officials said.

"Besides developing green lawns with a provision for a 3-km cycling tracks and walking area, the place has been given a historic look with interesting artwork. Landscaping of the place has been done in the Charbagh style with baradaris and chhatris derived from the vocabulary of the historic garden of the adjacent Qudsia Bagh," the official said.

"A 250-kg metal bell, sourced from famous craftsmen in Jalesar, Rajasthan, is installed near the entrance. Huge elephant structures made of pink Kota stone are another attraction," the official added. At the revamped central verge of Ring Road facing this ghat, similar kinds of sculptures can be seen installed, giving an all-new look to this place.

Besides, approximately 1,700 additional riverine native and naturalised species have been planted along the floodplain to develop a bountiful natural space at Vasudev Ghat.

The new ghat has stairs going down towards the river where people will be able to sit and enjoy a view of the Yamuna. While these steps have been constructed, their plaster work was pending on Friday. At the site, labourers were busy in levelling work next to the walking area as well.

The riverfront of the ghat will be around 150 metres long, officials said. The authority also proposes to make a changing area at the ghat in the future that people can use after bathing.

In Jan, the LG visited the place to attend a religious event and check the status of works here.

Work on Vasudev Ghat started last year, officials said. It was severely impacted due to the flooding Yamuna in Aug last year. Officials said that around one-and-a-half-foot layer of silt was collected from in and around the baradaris and other structures developed at the ghat.

"It took some time to clean the area and restart the development work, which pushed the deadlines back. As soon as work is complete here, focus will be on restoration and development of Sur Ghat near Wazirabad, in phase 2," an official said.

The development of Vasudev Ghat is a part of the 10 projects for restoration of the Yamuna floodplain on either side of the river. DDA has already developed places like Baansera and Asita along the river.

हिन्दुस्तान

रैट माइनर ने भूख हड़ताल का ऐलान किया

नई दिल्ली। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को बाहर निकालने में मदद करने वाले रैट माइनर वकील हसन ने इंसाफ न मिलने पर सोमवार से परिवार संग भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। वकील हसन ने बताया कि 28 फरवरी को उनके खजूरी खास के श्री राम कॉलोनी स्थित मकान को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अनाधिकृत बताकर ध्वस्त कर दिया था।

डीडीए फ्लैटों के संबंध में कॉल सेंटर पर संपर्क करें

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना में फ्लैटों की बुकिंग व पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। फ्लैटों के बारे में हर तरह की जानकारी के लिए नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। नोडल अधिकारी लोगों की समस्या को सुलझाएंगे।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

आज अमित शाह करेंगे पीएनजी सुविधा का शुभारंभ

अमित शाह •

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत यहां के 41 गांवों में पीएनजी सुविधा का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह 383 करोड़ रुपये की लागत से 178 गांवों में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम द्वारका के यशोभूमि केंद्र में होगा। कार्यक्रम में एलजी वीके सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत एलजी सक्सेना ने दिसंबर 2023 में की थी। इसका मकसद ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श करके गांवों की विकास योजना तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना है। इस अभियान के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से काम कर रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
Hindustan Times
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, MARCH 11, 2024
millenniumpost
pioneer
THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MARCH 11, 2024

Strong resolve for clean and green energy for Delhi

Dilli Gramodaya Abhiyan

Inauguration of

PNG facility in 41 villages of Delhi & various development works in 178 villages with an outlay of Rs. 383 Crore.

गाँव-गाँव PNG PIPED NATURAL GAS

"Our government is leaving no stone unturned to fulfill the aspirations of citizens in Delhi."

– Narendra Modi
Prime Minister

KEY BENEFITS:

• With 24x7 availability, PNG is safe, affordable & eco-friendly • Various development works are proposed to enrich the lives of villagers • Better roads, Development & maintenance of ponds/ water bodies • Sewage Treatment Plants • Drinking water facilities • Drainage works & provision of Rainwater harvesting system • Parks, playgrounds & community facilities • Village libraries, Street lights, CCTV Cameras • Charagah for fodder • Afforestation alongside roads/ public spaces, etc. • Rs. 383 crores sanctioned in just 3 months for urbanized villages.

Chief Guest

Shri Amit Shah

Hon'ble Union Minister of Home Affairs & Cooperation

आगे बढ़ें PNG चुनें PIPED NATURAL GAS

Guest of Honour

Shri Vinai Kumar Saxena

Hon'ble Lt. Governor, Delhi

11th March 2024 | Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi | 04:00 PM

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
दैनिक जागरण नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024
अमर उजाला
पंजाब केसरी DELHI
। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 11 मार्च 2024

दिल्ली के लिए स्वच्छ और हरित उर्जा का मज़बूत संकल्प

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत

दिल्ली के 41 गांवों में पाईपलाइन द्वारा रसोई गैस (PNG) की सुविधा एवं 178 गांवों में 383 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्यों का

शुभारम्भ

गाँव-गाँव PNG
PIPED NATURAL GAS

"केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शानदार, सुविधा सम्पन्न शहर बनाएं"

– नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

योजना के मुख्य लाभ:

• पी.एन.जी. 24x7 उपलब्धता के साथ सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है • ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अनेक विकास कार्यों का प्रावधान • बेहतर सड़कें, तालाब, जल निकायों का विकास एवं रखरखाव • सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेयजल सुविधाएं • ड्रेनेज कार्य एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली • पार्क, खेल के मैदान और सामुदायिक सुविधाएं • ग्राम पुस्तकालय, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे • चारे के लिए चरागाह • सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के किनारे वृक्षारोपण इत्यादि • मात्र 3 माह में शहरीकृत गांवों के लिए 383 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

मुख्य अतिथि

श्री अमित शाह

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

के कर कमलों द्वारा

विशिष्ट अतिथि

श्री विनय कुमार सक्सेना

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

आगे बढ़ें PNG चुनें
PIPED NATURAL GAS

11 मार्च 2024, सोमवार | यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली | दोपहर 04 बजे